



# सुप्रीम कोर्ट के मु. न्यायाधीश गवई ने चेताया राज्यपालों की भूमिका पर

मुख्य न्यायाधीश ने नेपाल का उदाहरण देकर कहा, अगर सरकार के दो स्तम्भों, विधायिका व प्रशासन में आपस में गतिरोध अनियंत्रित रहे तो उसका परिणाम अस्थिरता व अनिश्चितता होती है, जो पड़ोसी देश नेपाल में देखी जा रही है।

**- जाल खंबात -**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली 10 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक दुर्लभ और कड़ी टिप्पणी करते हुए केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है कि राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर विचार करते समय उसे भारत के पड़ोस, विशेष कर नेपाल, में हो रही घटनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने राष्ट्रपति से जुड़े एक संदर्भ की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसने राजनीतिक और क़ानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। कहीं चिंता जताई जा रही है तो कहीं इसे सही ठहराया जा रहा है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल के आदेश से जुड़ा है, जिसमें राज्यपालों और भारत के राष्ट्रपति के

- **जैसा कि, विदित ही है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला प्रस्तुत है, कि क्या राज्यपाल असीमित समय तक उनके सम्मुख विधानसभा से पारित विधेयक को पेंडिंग रख सकते हैं।**
- **मुख्य न्यायाधीश की इस मामले में चेतावनी जैसी टिप्पणी से विपक्ष काफी प्रसन्न है, तथा यह महसूस कर रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में उनके पक्ष व तर्क का मूक समर्थन किया है।**

लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने की समय सीमा तय की गई थी। इस फ़ैसले का मक़सद था, ऐसे विधेयकों पर अनिश्चित काल तक कोई कार्रवाई नहीं होने की प्रवृत्ति को रोकना।

केन्द्र की ओर से पेश हुए सांलिंसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपालों की विवेकाधिकार शक्तियों का जोरदार

विशेषज्ञों ने इसे नेपाल की ओर इशारा माना, जहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच बार-बार के टकराव ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेपाल का हवाला देना, याद दिलाने और चेतावनी, दोनों के तौर पर देखा जा रहा है, कि भारत सरकार को भी ऐसे संस्थागत टकराव से बचना होगा।

इस टिप्पणी ने तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कोर्ट की बात का स्वागत करते हुए मोदी सरकार से अपील की कि संघीय ढाँचे को कमज़ोर करने के खतरे को गंभीरता से लें। उनका कहना था कि राज्यपालों की विपक्ष-शासित राज्यों में विधायी प्रक्रिया रोकने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## विधायक ऋतु बनावत कैलाश यात्रा में फंसी

भरतपुर, 10 सितम्बर। विधायक ऋतु बनावत कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन-नेपाल बॉर्डर के पुरांग क्षेत्र में फंस गई हैं।

3 से 11 सितंबर तक की इस यात्रा के अंतिम चरण में नेपाल में चल रहे

- **नेपाल के अस्थिर हालात के कारण यात्रा दल को चीन - नेपाल बॉर्डर पर पुरांग क्षेत्र में रोक दिया गया।**

विद्रोह और अस्थिर हालात के चलते, यात्रा दल को रोक दिया गया है। राहत की बात है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैद म ने तुरंत एक्शन लिया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घबराएं नहीं, हर यात्री को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। ऋतु बनावत भरतपुर जिले के बयाना रूपवास क्षेत्र से विधायक हैं।

## नेपाल में 15,000 कैदी जेल से फरार

काठमांडू, 10 सितंबर। नेपाल में बीते दो दिनों में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उग्र लहर के चलते जेलों में बंद करीब 15 हजार से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं।

इसे विश्व इतिहास में जेल तोड़कर भागने की सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड के अनुसार इससे पहले 1979 में ईरान

- **हिंसक प्रदर्शनों के बीच आंदोलनकारियों ने जेलों पर धावा बोल दिया। इसमें 15,000 से ज्यादा कैदियों के भागने की खबर है। जेल से भागने की यह संभवतया इतिहास की सबसे बड़ी घटना है।**

में हुए तख्ता पलट में करीब 11 हजार कैदी भाग गए थे।

जेल तोड़ने की शुरुआत तब हुई जब युवा प्रदर्शनकारियों ने कई जेलों में धावा बोल दिया और उनके प्रशासनिक भवनों में आग लगा दी। इन लोगों ने जेल के दरवाज़े जबरन खोल दिए। बुधवार शाम तक, प्रारंभिक रिपोर्टों ने पुष्टि की कि 25 से ज्यादा जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी भाग गए थे, जिनमें से केवल कुछ ही स्वेच्छा से लौटे या उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया।

## पोलैण्ड ने रूस के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया

रूस ने, जैसा कि विदित ही है, अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया यूक्रेन पर, ड्रोन व हवाईजहाजों की बमबारी से

- **पोलैण्ड के हवाई क्षेत्र (एयर स्पेस) में जो ड्रोन पहुंचे, वो रूस के यूक्रेन पर किये गये भारी ड्रोन आक्रमण के, बिखरे हुए ड्रोन ही हैं।**
- **पोलैण्ड, नाटो देशों का आह्वान कर रहा है, कि वे अपने नाटो के सदस्य के रूप में किये वादे को पूर्ण करने की दृष्टि से अब रूस पर आक्रामक कार्यवाही करें।**
- **रूस इन वादों की पूर्ति तथा और आक्रामक होने की धमकी को कतई गंभीरता से नहीं ले रहा है।**
- **ये सब संकेत हैं, तृतीय विश्वयुद्ध की तारीख नज़दीक होने के।**
- **अमेरिका, यूरोपीय देशों को प्रोत्साहित कर रहा है, कि चीन व भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाये।**
- **हालात, सभी देशों को युद्ध की ओर घसीट रहे हैं।**

निर्णायक जीत दिखाने की बेचैनी में शत्रुता का स्तर बढ़ा रहा है और यूक्रेन को नुक़सान पहुंचा रहा है। अब पड़ोसी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

पोलैंड अब शत्रुता के विस्तार में सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है, और पोलैण्ड के आसमान में अब तक हुई घुसपैठ, उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन 'नाटो' को, अपने सामूहिक रक्षा समझौते को लागू करने की चुनौती दे रही है। नाटो सदस्य देशों ने संगठन में

शामिल होते समय शपथ ली थी कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा।

पुतिन यह संदेश दे रहे हैं कि वे किसी भी क़ीमत पर यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने पर आमादा है। तीव्र होते संघर्ष से वे यह जताना चाहते हैं कि अगर यूरोपीय सहयोगी अपने सैनिक भेजते हैं या और सक्रिय हस्तक्षेप करते हैं, तो वे उनसे भी लड़ने को तैयार हैं।

पश्चिमी यूरोपीय देशों ने ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## क्या नेपाल की पहली चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की मुखिया होंगी?

जैनरेशन ज़ैड ने सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया है पर अभी चर्चा चल रही है

**-डॉ. सतीश मिश्रा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 10 सितंबर। सरकार और राजनीतिक दलों के नेताओं के कथित भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर रही हैं। उनका नाम जेनरेशन ज़ैड द्वारा प्रस्तावित किया गया है और इस पर विचार-विमर्श अभी भी जारी है। युवा पीढ़ी के हिंसक प्रदर्शनों ने नेपाल को अराजकता में डाल दिया, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को कल इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद

### राजस्थान सरकार ने विशेष सैल बनाया व हैल्प लाइन नंबर जारी किये

जयपुर, 10 सितम्बर। नेपाल में हाल ही में हुई हिंसात्मक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वहां रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से सीधे बातचीत कर मौजूदा हालात की जानकारी ली और

- **मुख्यमंत्री भजन लाल ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से बात कर निर्देश दिए।**

आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि नेपाल में उत्पन्न हालात हृदय-विदारक हैं और राज्य सरकार वहां मौजूद हर राजस्थानी नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एक विशेष सैल का गठन किया गया है, जो नेपाल में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए कार्य ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## अमेरिका भी पूरी रुचि ले रहा है, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो और, उसका “आदमी” प्र.मंत्री की कुर्सी पर बैठे

अमेरिका ने अपने पिछलगू राजनीतिज्ञों में से तीन को चुना है प्र.मंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में

**-जाल खंबात-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 10 सितंबर। नेपाल में राजनीतिक नैतिकता की भारी कमी को लेकर लंबे समय से आक्रोश पनप रहा है। बीते 17 वर्षों में नेपाल में 14 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। आम धारणा यह है कि सभी दल सत्ता लोलुप, भ्रष्ट और भाई-भतीजावादी हैं। हर साल औसतन 8 लाख युवा नेपाल छोड़ते हैं, न केवल उच्च वेतन और मध्यम दर्जे की नौकरियों के लिए बल्कि दिहाड़ी मजदूरी तक के लिए। बेरोजगारी बहुत अधिक है और भयारी गरीबी है। यही कारण है कि देश में बड़े पैमाने पर असंतोष पनपा है। ओली सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध, जो कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल बाद लागू किया गया, जेनरेशन ज़ैड को स्वीकार नहीं था,

यह आखिरी तिनका साबित हुआ- जिसने सब्र का बांध तोड़ दिया। आज के उन्‍य देशों की तरह नेपाल में भी युवा अपनी भावना की अभिव्यक्ति, मनोरंजन और संवाद के लिए सोशल मीडिया निर्भर रहते हैं। ओली को नेपाल में एक अधिनायकवादी नेता के रूप में देखा जाता है। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने उस पर बैन लगाया। जिससे युवा वर्ग भारी नाराज हो गया और उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक कदम करार दिया।

इस पूरे घटनाक्रम में शासन परिवर्तन के ऑपरेशन के संकेत मिलते हैं। एक है रवि लामिछाने जो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे गए थे। मंगलवार को भीड ने ललितपुर

जिले के नक्खु जेल पर हमला कर 1500 कैदियों को छुड़ा लिया- इनमें रवि लामिछाने भी शामिल थे। उन्हें अमेरिका का करीबी माना

■ **पहला नाम है राबी लामिछाने का, ने कुछ समय के लिये, दिसम्बर 2022 से जनवरी 2023 तक, नेपाल के उपप्रधानमंत्री व गृह मंत्री रह चुके हैं तथा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार थे, पर युवा आंदोलनकारियों ने नाखु जेल तोड़कर सभी कैदियों को रिहा करवाया था, उनमें राबी लामिछाने भी थे।**

■ **दूसरा नाम काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह का है। शाह घोर भारत विरोधी विचारों के व्यक्ति हैं, और उनके ऑफिस में अखण्ड नेपाल का नक्शा लटका हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का काफी हिस्सा प्रस्तावित अखण्ड नेपाल में दिखाया गया है।**

■ **तीसरा नाम हरका समपंग का है, जो वर्तमान में धारन के मेयर हैं।**

■ **अमेरिका के समर्थन में नेपाल में दो और ताकतें हैं। नेपाल के इसाई, जिनकी संख्या अनियंत्रित धर्मपरिवर्तन से बहुत बढ़ी है, पिछले कुछ सालों में, और दूसरी ताकत है, एनजीओ जिन्हें अमेरिका से भारी आर्थिक मदद व अनुदान मिलता है। ये दोनों ताकतें भी चाहेंगी कि कोई अमेरिका का समर्थक ही प्र.मंत्री बने।**

जैसे हैं बालेन्द्र शाह उर्फ बालेना ये काठमांडू के मेयर हैं, जिन्हें भारत विरोधी रवैये के लिए जाना जाता